



2026:AHC:4351

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44682 सन् 2025

दिलशाद

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: राजेश कुमार शर्मा

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अरिमर्दन यादव, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 53 वर्ष 2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना गभाना, जिला अलीगढ़, में विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। गैंग चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिवृत्त को जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को गैंग चार्ट में उल्लिखित समस्त मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या संयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी गिरोह की गतिविधियों में सहयोग या सहायता नहीं की है। उक्त प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिवृत्त नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने अथवा साक्षियों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 28.02.2025 से जेल में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि स्वतंत्रता प्रदान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लम्बित मामलों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए विचारण का शीघ्र निस्तारण होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2020 (11) एससीसी 648**, में पारित निर्णय पर आश्रय लिया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों की लम्बितता स्वयं में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की जमानत का विरोध नहीं कर सके और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले के अतिरिक्त कोई अन्य मामला भी नहीं बता सके।

समस्त तथ्यों की समग्रता, साक्ष्य की प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुणावगुणता पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उचित मामला पाता हूँ। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उक्त वाद अपराध संख्या में आवेदक **दिलशाद** को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलके तथा उसी राशि की दो विश्वसनीय जमानतों पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- iii) आवेदक (i) मामले के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचन, तथा (iii) कथन अभिलिखित किए जाने हेतु निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iv) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- v) आवेदक विचारण न्यायालय में नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक ही सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले की गुणावगुणता पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

08 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)